हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 20 फरवरी, 2019

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

शोक प्रस्ताव

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
के काफिले पर कायराना आतंकी हमले से संबंधित निंदा प्रस्ताव

बैठक का स्थगन

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 20 फरवरी, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के अनुसार में, मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176–(1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 20 फरवरी, 2019 को 02.00 बजे मध्याह्न पश्चात हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है। माननीय राज्यपाल अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई ।)

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदो!

मैं 13वीं हरियाणा विधानसभा के सम्मानित सदस्यों का 5वें बजट सत्र के शुभारम्भ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हर्षित हूँ कि मेरी सरकार ने नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान किया है। जहां हर ओर इस नव सृजित माहौल की सराहना हो रही है, वहीं मेरी सरकार निरंतर युवाओं, वृद्धों, किसानों, जवानों– सभी की आकांक्षाओं के अनुरूप नये–नये और साहसिक प्रशासनिक सुधार कर रही है।

2. गत वर्ष हरियाणा ने देश में पहली बार केवल किसानों के हितों को समर्पित 'किसान कल्याण प्राधिकरण' का गठन किया, मण्डियों में लाये गये बाजरे के हर दाने की 1950 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सीधे किसानों के खातों में अदायगी की और गन्ने का सर्वाधिक 340 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया। अब शीघ्र ही, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत प्रदेश के साढ़े 10 लाख से अधिक लघु और सीमांत किसानों के हर परिवार को दो हजार रुपये की पहली त्रैमासिक किश्त का वितरण देश में सबसे पहले सुनिश्चित करने का कीर्तिमान भी हरियाणा स्थापित करने जा रहा है।

3. इस वष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप हरियाणा को ओडीएफ ++ बनाने के मेरी सरकार के संकल्प की घोषणा करते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। इससे पहले हमने अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को 2017 में खुले में शौच से मुक्त कर दिया था और वर्ष 2018 के ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा ने पूरे भारतवर्ष में शीर्ष स्थान हासिल किया।

4. पर्ची मुक्त और सिफारिश मुक्त तरीके से 56 हजार से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने से प्रदेश के लोगों में अद्भुत उत्साह है। लगभग 17,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साक्षात्कार खत्म करने तथा विधवाओं, अनाथों एवं अनाधिसूचित जन जातियों, जो न तो अनुसूचित जातियों और न ही अनुसूचित जनजातियों में आते हैं और जिन परिवारां का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, के लिए 10 प्रतिशत

अंकों के विशेष प्रावधान से दशकों से हताशा व निराशा से ग्रस्त मेधावी युवकों और वंचित दोनों वर्गों में एक नई आशा का संचार हुआ है। इन निर्णयों के पीछे सरकार की सोच को हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी सराहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उम्मीदवारों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का मेरी सरकार का गत सप्ताह का निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है।

5. हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने गोल्ड कोस्ट, आस्ट्रेलिया में आयोजित 21वें राष्ट्रमण्डल खेलों में भारत के राज्यों में सर्वाधिक 22 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल थे। इंडोनेशिया में आयोजित 18वें एशियन खेलों में भी राज्य के खिलाड़ियो ने कुल 17 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इस वर्ष 1166 खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एचसीएस तक की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिये नियम अधिसूचित किये गये हैं।

6. मेरी सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति को पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए महत्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत' योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाया जाता है, को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत अब तक पांच लाख से अधिक नागरिकों को पंजीकृत किया गया है और 357 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। अब तक लगभग सात करोड़ रुपये की राशि के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार 10.54 लाख गरीब परिवारों को दो लिटर सरसों का तेल के साथ 8.04 लाख गरीब परिवारों को एक किलोग्राम चीनी प्रतिमाह रियायती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 13 लाख 84 हजार से अधिक एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध करवाय गये हैं। राज्य में गरीब और मजदूरों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 'अंत्योदय आहार योजना' शुरू की गई है। सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाला, करनाल और भिवानी में सस्ते भोजन की कैंटीन स्थापित की गई हैं। ये सफलतापूर्वक चल रही हैं तथा प्रदेश में 14 और कैंटीन स्थापित की जा रही हैं।

7. गांवों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना शुरू की गई है, जिसमें 1122 ग्राम पंचायतों को पहले ही वर्गीकृत किया गया है। शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत शमशान घाटों का नवीनीकरण करने, शैड बनाने, पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने, शमशानघाटों की चारदीवारी बनाने और शमशानघाटों तक सड़कें बनाने की लोगों की चिरलम्बित मांगों को पूरा किया जा रहा है।

8. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा हरियाणा से शुरू किये गये 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम को सफल बनाने के हमारे व्यापक अभियान के सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं और लिंगानुपात वर्ष 2018 में बढ़कर 914 हो गया है। अत्यंत हर्ष की बात है कि 48 गांवों में लिंगानुपात 953 और 1000 के बीच पहुंच गया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक

लागू करने के लिए हमारे प्रदेश को चार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। 'आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना' के तहत 34,130 बालिकाओं के जन्म पर उनके खातों में 21,000 रुपये की राशि प्रति बालिका जमा करवाई गई है। परिपक्व होने पर लगभग एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'दुर्गा शक्ति एप्प' शुरू किया गया है और 'दुर्गा शक्ति वाहिनी' और एक विशेष बल 'दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स' का गठन किया गया है। एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं व लड़कियों के लिए एक नई पैंशन स्कीम शुरू की गई है जो दिव्यांग पेंशन का अधिकतम 4.5 गुणा बढ़ाई गई है।

9. हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि हमारा राज्य, भारत सरकार की निवेशक फीड बैक रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के लिए पंसदीदा राज्य बन गया है। हमारे राज्य को पर्यावरण व श्रम से संबंधित सुधारों को लागू करने तथा हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के लिए शीर्ष स्थान मिला है। निवेशक मैत्री माहौल उपलब्ध करवाने में मेरी सरकार ने सर्वोत्तम वैश्विक मानकों को पार कर लिया है तथा भारत सरकार द्वारा जारी ईज–ऑफ–डूईंग बिजनेस की रैंकिग में हरियाणा वर्ष 2015 के 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है तथा उत्तर भारत के राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

10. विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों, राज्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रकोष्ठ ने विभिन्न प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों व प्रसिद्ध उद्योगों के साथ 250 से अधिक समझौते किये हैं। विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके, नौकरी के लिए तैयार करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख कॉरपोरेट इकाइयों जैसकि मारुति, हीरोकोर्प, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डेफोडिल इंडिया के सहयोग से पांच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

11. मेरी सरकार राज्य में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई वर्षों से अधर में लटकी कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेस–वे परियोजना का कार्य पूरा करके इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। बहादुरगढ़–मुण्डका और बल्लबगढ़–फरीदाबाद दो नई मैट्रो रेल सेवाएं शुरू की गई हैं। मेरी सरकार हिसार मं 4200 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन हब के चरणबद्ध विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य योजना पर काम कर रही है। मेरी सरकार गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में हरियाणा का पहला एम्स स्थापित करने की केन्द्रीय बजट–2019 में की गई घोषणा के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करती है। जिला झज्जर के गांव बाढ़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान व फरीदाबाद में ईएसआई अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय के उद्घाटन तथा जिला करनाल के कुटैल में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय तथा पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शिलान्यास करने के लिए हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है।

12. मेरी सरकार एसवाईएल के निर्माण के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध है। इसके साथ ही यमुना और इसकी सहायक नदियों से हरियाणा राज्य के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के अपस्ट्रीम पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ बांधों के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है। इनका निर्माण कार्य पूरा होने पर हमारे राज्य को लखवाड़ और रेणुका बांध परियोजनाओं से कुल जल संग्रहण का 47.81 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। मरी सरकार ने 'हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण' का गठन किया है। यह प्राधिकरण तालाबों के विकास, संरक्षण, जीर्णोद्धार, निर्माण और तालाबों के प्रबंधन तथा सीवेज मलशोधन संयंत्रों के जल सिंचाई के लिए उपयोग करने के कार्य करेगा, जिससे भूजल के अत्यधिक दोहन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर दबाव कम होगा।

13. सभी गांवों को 24X7 घण्टे बिजली देने की सोच के दृष्टिगत 'म्हारा गांव–जगमग गांव योजना' के तहत पंचकूला, अम्बाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के सभी गावों को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। गत तीन वर्षों में वितरण कंपनियों का सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा 30.02 प्रतिशत से घटकर 20.29 प्रतिशत रह गया है। इसका लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए मेरी सरकार ने पहली अक्तूबर, 2018 से हर माह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें लगभग आधी कर दी हैं। किसानों को राहत देते हुए 92,000 से अधिक कृषि नलकूप कनैक्शन देने का निर्णय लिया है।

14. बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए 20 सितम्बर, 2018 को 'बिल निपटान योजना' शुरू की गई, जिसके तहत जून, 2005 से पहले के सभी बकाया बिलों को माफ कर दिया गया है। इस स्कीम को 11.15 लाख उपभोक्ताओं ने अपनाया और 368.63 करोड़ रुपये जमा करवाए। 2932.58 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई और कुल 3301.21 करोड़ रुपये का निपटान किया गया।

15. मेरी सरकार ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद फरीदाबाद शहर की व्यापक योजना और विकास के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया है। सड़कों, सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में 671 कालोनियों को नियमित किया गया है। सस्ती आवास नीति 'दीनदयाल जन आवास योजना' के तहत वर्ष 2018–19 में 1331 एकड़ क्षेत्र के लिए 135 से अधिक लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉटधारकों द्वारा देय भारी वृद्धि के चिरलंबित मामलों को हल करने के लिए मेरी सरकार ने 'एकमुश्त निपटान योजना' और 'पूर्ण एवं अंतिम भुगतान निपटान योजना' शुरू की, जिसके तहत आबंटियों को लम्बित बढ़े हुए बकायों का क्रमशः 60 प्रतिशत और 62.5 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा के साथ शेष क्रमशः 40 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत राशि माफ करने का लाभ दिया गया। कुल 29,000 से अधिक आबंटियों ने आवेदन किया और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को केवल 981 करोड़ रुपये का भुगतान करके 654 करोड़ रुपये का लाभ उठाया। राज्य में 35 शहरों की विकास योजनाओं को अब अंतिम विकास योजनाओं के रूप में प्रकाशित

किया जा चुका है। शहरी लोगों को राहत देने के लिए चौथी मंजिल तक आवासीय मकान बनाने की अनुमति दी गई है। शिक्षा क्षेत्र को गति देने के लिए कृषि क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के लिए सीएलयू की शर्तों में ढील दी गई है।

16. हमारे स्वतंत्रता प्रेमी लोगों द्वारा किये गये संघर्षों और सहे गये कष्टों को मान्यता देने की नीति पर चलते हुए मेरी सरकार ने मातृभाषा हिन्दी सत्याग्रहियों और उनकी विधवाओं को प्रतिमास 10,000 रुपये मासिक पेंशन देनी शुरू की है। आपातकालीन पीड़ितों, मातृभाषी हिन्दी सत्याग्रहियों को अब पांच लाख रुपये तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मेरी सरकार ने सभी प्रकार की सामाजिक पेंशनों जैसेकि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा और निराश्रित पेंशन आदि बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमास कर दी है। सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए राज्य में 'हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग' गठित किया गया है। मेरी सरकार ने वर्तमान वित्तीय लाभों के अलावा सीमाओं पर मुठभेड़ों, आतंकवादी हमलों या दंगों में सशस्त्र बलों व अर्ध सैनिक बलों के हरियाणा के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर अब हरियाणा सरकार में श्रेणी 'बी' तक के पदों पर नियुक्तियां देने का निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास

17. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के अंतर्गत मेरी सरकार ने हर वर्ष प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 2.00 करोड़ रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि एक या एक से अधिक गांवों में खर्च की जा सकती है। विधायक द्वारा चुने गये हरेक व्यक्तिगत गांव के लिए निर्धारित तीन स्लैब में से एक स्लैब की सीमा होगी। यदि किसी गांव की आबादी 5,000 तक है तो उसे 50 लाख रुपये, यदि आबादी 5,000 से अधिक व 10,000 तक है तो उसे 1.00 करोड़ रुपये तथा यदि आबादी 10,000 से अधिक है तो उस गांव को 2.00 करोड़ रुपये 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के तहत दिये जाते हैं।

18. 'श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' के तहत राज्य के साथ–साथ लगते 152 हुए गांवों के 10 समूहों की तीन चरणों में पहचान की गई है। ये समूह आर्थिक गतिविधियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता प्रदान करके विकसित किये जाएंगे। इनके विकास पर तीन से पांच वर्षों में 884.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

19. गरीबी कम करने के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों की 1,11,000 से अधिक महिलाओं ने अपने सामाजिक व आर्थिक स्वावलंबन के लिए रिकार्ड संख्या में 12,033 स्वयं सहायता समूह गठित करने का सराहनीय कार्य किया है। जिला करनाल के स्टौंडी गांव के एक ग्राम संगठन 'संगम महिला संगठन' को स्वयं सहायता समूहों के सर्वोत्तम कार्यों के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ संगठन घोषित किया गया है तथा उसे दो लाख रुपये का नकद पुरस्कार व एक प्रशस्ति–पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

विकास एवं पंचायत

20. पूर्ण रूप से शिक्षित पंचायतां के चुनाव के कारण हमारे राज्य में एक काया पलट परिवर्तन के बाद मेरी सरकार निधि, कार्य और पदाधिकारी प्रदान करके पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब तक बस क्यू शैल्टर के निर्माण और रखरखाव, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य जिला परिषदों को सौंपा गया है तथा व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य पंचायत समितियों को दिया गया है।

21. मेरी सरकार ने वर्ष 2015–16 से आज तक 1801 ग्राम सचिवालय स्थापित किये हैं ताकि ग्राम स्तर के सभी अधिकारी जैसे कि ग्राम सचिव, राजस्व पटवारी, कृषि विकास अधिकारी और बिजली विभाग का सहायक लाइन मैन एक कार्यालय में बैठ सकें।

22. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगस्त, 2018 में भारत सरकार द्वारा किये गये 'ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण' में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल जिलों को उत्तर क्षेत्र में स्वच्छ जिलों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान मिला है। अब मेरी सरकार ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है, जिसके लिए 376 करोड़ 85 लाख रुपये लागत की 1372 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 662 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं तथा 469 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार गोबर और कचरे की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में 'गोबर गैस संयंत्र' स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

23. पिछले वर्ष घोषित 'दीनबंधु ग्राम उदय योजना' के तहत 963 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं और नाबार्ड द्वारा 480 आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु 40 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ग्राम ज्ञान केन्द्रों के लिए 210 करोड़ रुपये की तथा पशु अस्पतालों व डिस्पेंसरियों के लिए 47 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृति के लिए नाबार्ड को भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने 'किसान खेत सड़क योजना' के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

शहरी स्थानीय निकाय

24. मेरी सरकार ने सम्पूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों में उच्चकोटि का इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। तीन चयनित शहरों–फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी परियोजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही ह। फरीदाबाद में 283 करोड़ रुपये की लागत की अभिनव परियोजनाएं जैसेकि स्मार्ट शौचालय, ओपन एयर स्मार्ट जिम, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र इत्यादि शुरू की गई हैं। इस मिशन के तहत करनाल में 1211 करोड़ रुपये की लागत की 58 परियोजनाओं की पहचान की गई है। शहरो चौकसी, सिटी बस सेवा और कर्ण पार्क के जीर्णोद्धार की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा 154 करोड़ रुपये की लागत के अन्य कार्य प्रक्रियाधीन हैं। फरीदाबाद में सार्वजनिक परिवहन की

आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्ट्रा सिटी बस सेवा शुरू की जा रही है। प्रथम चरण में 166 किलोमीटर के 19 रूटों पर चलाने के लिए 90 बसें खरीदी जा रही हैं।

25. मेरी सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। दो कलस्टर नामतः गुरुग्राम–फरीदाबाद और सोनीपत–पानीपत के लिए परियोजना गतिविधियां आरंभ की गई हैं। पंचकूला क्लस्टर के लिए सशर्त स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। तीन क्लस्टरों नामतः रेवाड़ी, भिवानी और फतेहाबाद के लिए तकनीकी बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। गुरुग्राम में निर्माण एवं तोड़फोड़ के मलबे के प्रसंस्करण की सुविधा विकसित की जा रही है तथा अन्य निगमों में ऐसी सुविधा विकसित करने की योजना बनाई गई है।

26. अमरूत योजना के तहत प्रत्येक घर में जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शन सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने राज्य के 18 शहरों के लिए 2565 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की है, जिसमें से 2274 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत के 41 कार्य आबंटित कर दिये गये हैं। राज्य को भारत सरकार द्वारा अमरूत योजना के तहत विभिन्न नगरपालिका सुधारों के लिए प्रशस्ति–पत्र भी दिया गया है। अमरूत योजना के 17 नगरों में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित मास्टर प्लान और उपयोगी मानचित्रण तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। मेरी सरकार ने स्वर्ण जयंती पार्क योजना के तहत 50 पार्कों का विकास करने का निर्णय लिया है, जिनके लिए 29 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

27. विभिन्न आईटी पहलों के तहत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, भवन निर्माण योजना स्वीकृति, अग्निशमन सेवाएं, कारोबार लाइसेंस इत्यादि जैसी 120 सेवाएं सरल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई हैं। सम्पत्ति कर को सुचारू बनाने के लिए राज्य में केन्द्रीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित सम्पत्ति कर सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो प्रत्येक परिवार को सम्पत्ति की अनूठी पहचान के साथ भूखण्डों के परिमाप की सटीक स्थिति उपलब्ध करवाएगा। यह प्रणाली स्थानीय निकायों के राजस्व में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि करने और नगरपालिका प्रशासन में अनुचित भेदभाव समाप्त करने में सक्षम होगी।

28. मेरी सरकार ने छोटे और सीमांत दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेहड़ी–फड़ी लगाने के क्षेत्रों की पहचान की है तथा राज्य के सभी 80 नगरों में एक विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से पहचान किये गये एक लाख से अधिक शहरी रेहड़ी–फड़ी वालों को रेहड़ी के लिए स्थल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

29. शहरों में बेघरों की स्थिति देखते हुए एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें 19,015 बेघरों की पहचान की गई है, जिसके लिए 103 रैन बसेरों का उन्नयन किया जा रहा है तथा 39 सचल कैबिन बसेरे स्थापित किये गये हैं। राज्य में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 134 अग्निशमन वाहनों व 18 कोम्बी टूल व अग्निशमन उपकरण खरीदे गये हैं।

आवास

30. मेरी सरकार के कार्यकाल के दौरान बोर्ड ने 19,356 आवास इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है । इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक आवास इकाइयां गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड ने 1,218 आवास इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा किया है और 1,270 आवास इकाइयां निर्माणाधीन हैं। गुरुग्राम में हाल ही में 1,719 ईडब्लयूएस मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

31. बोर्ड ने अपनी भावी आवास परियोजनाओं के लिए 'हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण' और शहरी स्थानीय निकाय विभाग से ईडब्लयूएस श्रेणी के लिए 220 एकड़ भूमि तथा प्रतिरक्षा श्रेणी के लिए 87 एकड़ भूमि खरीदी है। बोर्ड ने बीपीएल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से 11,239 ईडब्लयूएस प्लॉट खरीदे हैं। ईडब्लयूएस श्रेणी के तहत आवास इकाइयों के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी भी पात्र हैं।

नगर एवं ग्राम आयोजना

32. आम जनता के हित में लाइसेंसशुदा कालोनियों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निर्धारित प्लॉट और फ्लैट के आवंटन के लिए 17 मई, 2018 को एक व्यापक नीति तैयार की गई है। आवासीय प्लॉटिड कॉलोनियों में 20 प्रतिशत प्लांट और ग्रुप हाऊसिंग कॉलोनियों में 15 प्रतिशत आवासीय फ्लैट ईडब्लयूएस के लिए आरक्षित होंगे। दोनों ही मामलों में आवंटन आवास बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

33. मेरी सरकार दिल्ली से गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लबगढ़ और बहादुरगढ़ तक मैट्रो लाइन के विस्तार के लिए 3500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पहले ही कर चुकी है। हरियाणा में मैट्रो परियोजनाओं को और बढ़ावा देने के लिए छः परियोजनाओं नामतः नरेला से कुंडली, फरीदाबाद से गुरुग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सिटी सैंटर से रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ से सांपला, बाढ़सा से द्वारका और गुरुग्राम में दक्षिणी परिधि सड़क पर मैट्रो का विस्तार करने पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

राजस्व

34. वर्तमान अनुमानिक भूमि स्वामित्व प्रणाली से निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली को अपनाने, जिसमें सरकार भूमि स्वामित्व की गारंटी देती है, के दृष्टिकोण के तहत राज्य ने वैब– हैलरीस नामक एक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन एकीकृत कार्य गति आधारित संपत्ति पंजीकरण और भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। डिजीटल व आईटी पहलों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप मेरी सरकार ने वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में 1005 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आया है और पिछले वर्ष 15 फरवरी 2018 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 15 फरवरी 2019 तक 1327.07 करोड़ रूपये की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में लेन–देन में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई ।

35. कैथल, जींद आर सोनीपत में आधुनिक राजस्व रिकार्ड कक्ष स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों में 76 करोड़ के परिव्यय से इस पहल का विस्तार किया जा रहा है। राज्य ने सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों की ई–फर्द के लिए एक वैब एप्लीकेशन विकसित की है, जिसमें 2 लाख से अधिक परिसंपत्तियां व संपत्तियां दर्ज की गई हैं।

36. मेरी सरकार ने ई–गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। सभी पटवारियों को ई–गिरदावरी करने के लिए टैबलेट दिए गए हैं। खरीफ फसल–2018 में हर जिले की एक तहसील के सभी गांवों की इन टैबलेट का प्रयोग करके ई–गिरदावरी की गई। आगामी रबी फसल–2019 में सभी तहसीलों और उप–तहसीलों को कवर करने के लिए ई–गिरदावरी का दायरा बढ़ाया जाएगा।

37. राज्य ने खरीफ फसल–2018 में बाजरे की फसल के लिए देश में अपनी तरह की पहली पहल के रूप में 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' वैब एप्लीकेशन भी शुरू की है।

38. आपातकालीन राहत के तहत, राज्य ने उन किसानों को भी राहत देने का फैसला किया है, जिनकी भूमि पर खरीफ 2018 के दौरान जल भराव के कारण बिजाई नहीं की जा सकी। नम्बरदारों का मौजूदा मासिक मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर दोगुणा करके 3000 रुपये किया गया है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

39. यमुना नदी के जल का अधिकतम संभव उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष ''पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने'' की परियोजना शुरू की गई। इससे पहले की विद्यमान 8800 क्युसिक क्षमता को बढाकर 13300 क्युसिक किया जाना है। इससे दक्षिणी हरियाणा की पानी की जरूरतें पूरी होंगी और निकट भविष्य में जेएलएन फीडर की जल प्रवाह क्षमता बढ़ाकर इसकी निर्धारित क्षमता 3541 क्युसिक तक की जाएगी। आंशिक क्रियान्वयन से वर्तमान क्षमता बढ़ाकर 10 हजार क्युसिक से अधिक किया गया है। फलस्वरूप सभी टेलों, पर यहां तक कि दक्षिणी हरियाणा की टेलों पर भी पानी पहुंच रहा है।

40. मेरी सरकार ने "हर खेत को पानी" के विजन को साकार करने के लिए सिंचाई के क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत बदलावों की पहल की है, जिसके तहत सिंचित क्षेत्र में पक्के जलमार्गों को 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ किया जाएगा।

बिजली

41. मेरी सरकार ने प्रदेश में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पिछले 4 वर्षों के दौरान 29 नए सब–स्टेशन स्थापित किय गये हैं और 257 वर्तमान सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। सम्प्रेषण क्षमता में 9892 एमवीए की वृद्धि की गई है और 1110 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं।

42. वर्ष 2019–20 में सम्प्रेषण प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के लिए 19 नये सब–स्टेशन स्थापित करने, 89 वर्तमान सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने तथा 1000 किलोमीटर लम्बी नई सम्प्रेषण लाइन बिछाने की योजना है।

43. बिजली के उचित वितरण के लिए पिछले चार वर्षों में दिसंबर 2018 तक 33 केवी के 140 नए सब–स्टेशन स्थापित किये गये हैं। वर्तमान 386 सब–स्टेशनां की क्षमता बढ़ाई गई है और 33 केवो की 1555 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाई गई हैं। आगामी वर्ष में 33 केवी सब–स्टेशनों के तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 95 नए सब–स्टेशन स्थापित करने, 107 वर्तमान 33 केवी सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और 33 केवी की 700 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाने की योजना है।

44. सरकार द्वारा स्वच्छ सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के विभिन्न स्थलों पर कुल 57 मेगावाट के जमीन पर सोलर पावर प्लांट और नहरों पर 16 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की गई है।

नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा

45. मेरी सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए राज्य में फसल अवशेषों के कुशल निपटान के लिए बॉयोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक निवेशक अनुकूल हरियाणा जैव–ऊर्जा नीति 2018 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट क्षमता की जैव ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना है।

46. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छतों पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। चालू वर्ष में ग्रिड से जुड़े 18 मेगावाट क्षमता के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य की 278 गौशालाओं में 1606 किलोवाट के ग्रिड से जुडे और ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लगाने की परियोजना भी शुरू की गई है। किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य में सौर ऊर्जा चालित 2300 पंप स्थापित किए जा रहे हैं। नाबार्ड के ऋण से 3एचपी से लेकर 10एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सौर पंप स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन पर राज्य 75 प्रतिशत सबसिडी देगा।

47. राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण सबसिडी के बोझ को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने वर्तमान विद्युत चालित नलकूपों को सौर ऊर्जा चालित करने की योजना बनाई है। जनता की प्रकाश ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,00,000 'मनोहर ज्योति' नामक सौर ऊर्जा गृह प्रणालियां उपलब्ध करवाने की भी योजना बनाई गई है। हर प्रणाली पर 15,000 रुपये की सबसिडी दी जाएगी। हर प्रणाली में 2 एलईडी ल्यूमिनेयर, एक एलईडी ट्यूब लाइट, 1 डीसी सीलिंग फैन और मोबाइल चार्जिंग के लिए 1 यूएसबी पोर्ट का प्रावधान होगा। गांवों में 10,000 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की परियोजना भी शुरू की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास

48. लिंग समानता के लक्ष्यों को हासिल करने तथा महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार केन्द्र सरकार की सहायता से अनेक योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल विकास योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण योजना, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र चला रही है।

49. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किश्तों में पांच हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में 2,11,835 लाभानुभोगियों को 82.66 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के साथ–साथ सभी जिलों में पोषण अभियान चलाया जा रहा है तथा इस समय 8.27 लाख बच्चों व 2.59 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस कार्यक्रम के तहत लाभांवित किया गया है।

50. सात जिलों में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किये गये हैं, जो प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे समेकित समर्थन एवं सहयोग प्रदान करते हैं और चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श समेत तत्काल, आपातकालीन और गैर–आपातकालीन सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों में महिलाओं और उनके बच्चों के 3,528 मामलों का निपटान किया गया है।

कृषि

51. मेरी सरकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुणा करने के विजन का अनुसरण कर रही है। जिन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किये गये हैं, उनकी भारी मात्रा में खरीद करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इस खरीद के लिए ई–खरीद पोर्टल (मेरी फसल–मेरा ब्यौरा) पर किसानों का पूर्व पंजीकरण किया जाता है। वित्त वर्ष 2018–19 में सरसों की 2.70 लाख टन और बाजरे की 1.80 लाख टन की रिकार्ड खरीद की गई है।

52. राज्य सरकार ने चार बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बाजार भाव अत्यधिक गिरने की स्थिति में किसान को कम से कम उसकी उत्पादन लागत अवश्य मिले। इस वर्ष भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक 21,573 किसानों का पंजीकरण किया और 2.58 करोड़ रूपये भाव में अन्तर के रूप में दिये गये ।

53. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नई विशेष मण्डियां स्थापित की जा रही हैं। पिंजौर की अति आधुनिक समेकित सेब मण्डी का शिलान्यास किया जा चुका है। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय थोक मण्डी के निर्माण और संचालन के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है। आगामी वर्ष में शेरसा, कुण्डली में मसालों की और गुरुग्राम में फूलों की थोक मण्डियां स्थापित की जाएंगी।

प्रदेश की 54 मंडियों को ई–नाम से जोड़ने में हरियाणा एक अग्रणी राज्य है। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल रहे हैं।

54. मेरी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु नई कृषि पद्धतियां अपनाकर और मशीनरी उपलब्ध करवाकर खरीफ 2018 में एक व्यापक अभियान चलाया। 80 प्रतिशत की सबसिडी के साथ 1,194 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। 3,666 व्यक्तिगत किसानों को 17.83 करोड़ रुपये के बजट से 50 प्रतिशत अनुदान पर मशीनरी दी गई। हमारे राज्य में किसानों के सक्रिय सहयोग से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है।

55. मेरी सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास के लिए होडल में एक नया एकीकृत उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया है। चालू वर्ष के दौरान हरियाणा भाण्डागार निगम द्वारा 45,020 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। अगले वर्ष इसमें 27,112 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता जोड़ी जाएगी। निगम ने पीपीपी मोड पर 6.0 लाख मीट्रिक टन क्षमता की स्टील की बुखारियां बनाने का काम हाथ में लिया है। भारत सरकार ने राज्य में तीन चरणों में 9. 50 लाख मीट्रिक टन की क्षमता की स्टील की बुखारियां के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पशुपालन और डेयरी

56. मेरे राज्य में चालू वर्ष के दौरान नवम्बर 2018 तक कुल दुग्ध उत्पादन 68.48 लाख टन तक पहुंच गया है, जोकि 9.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत 375 ग्राम की तुलना में 1100 ग्राम तक पहुंचने की आशा है। हमारा राज्य देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नवम्बर 2018 तक अंडों का उत्पादन 40,408 लाख रहा, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान अंडों का उत्पादन 37,309 लाख था। इस प्रकार अंडों के उत्पादन में 8.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में 108 लाख टन दूध का तथा 59,765 लाख अंडों का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

57. राज्य में पशु पालकों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चालू वर्ष के दौरान प्रदेश में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा' योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पशु पालक प्रत्येक पशु के बीमे के लिए 100 रुपये का भुगतान करके एक वर्ष के लिए अपने पांच बड़े पशुओं का बीमा करवा सकता है अथवा वह प्रत्येक पशु के लिए 25 रुपये का भुगतान करके एक वर्ष के लिए 50 छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है। बड़े पशुओं के लिए बीमा कवरेज 1,25,000 रुपये तक तथा छोटे जुगाली करने वाले पशुओं (भेड़ एवं बकरियों) और सुअरों के लिए 5,000 रुपये है।

58. समाज के वंचित वर्गों को अपनी आजीविका के लिए पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुसूचित जाति के परिवारों को डेयरी, सुअर, भेड़ और बकरी पालन की इकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी का विशेष प्रावधान किया गया है। अन्य जातियों के लोगों को सुअर, भेड़ और

बकरी पालन की इकाइयों की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है।

59. राज्य में पशुपालकों को दूरभाष से घर–द्वार पर पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जींद, मेवात और यमुनानगर जिलों में पायलट आधार पर 'पशु संजीवनी सेवा' शुरू करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मत्स्य पालन

60. माननीय सभासदो! हमारा राज्य प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादकता में देश में दूसरे स्थान पर है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा हमारे राज्य को 'मत्स्य रोग मुक्त राज्य' घोषित किया गया है। सघन मत्स्य पालन के तहत लगभग 20,000 हैक्टेयर जल स्रोत हैं और राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2.28 लाख मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन होता है। मेरी सरकार प्रति हैक्टेयर 11,000 किलो ग्राम मत्स्य उत्पादन के मौजूदा स्तर को बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन प्रबंधन और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगी।

61. मेरी सरकार ने खारे पानी में बड पैमाने पर मत्स्य पालन के लिए जल क्षेत्र में वृद्धि करने की योजना बनाई है। मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए आगामी वर्ष के दौरान जिला झज्जर, जींद और चरखी–दादरी के जल भराव क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।

62. मोती की खेती की दो इकाइयां स्थापित की जाएंगी और हरियाणा के 15 सरकारी मत्स्य बीज फार्मों पर 935.00 लाख फिश फिंगरलिंग्स का उत्पादन किया जाएगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

63. मेरा राज्य खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद में एक अधिशेष राज्य है। रबी विपणन सीजन 2018–19 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय भण्डार के लिए 87.54 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। गेहूं की यह खरीद अब तक की सर्वाधिक है। खरीफ विपणन सीजन 2018–19 के दौरान सामान्य और ग्रेड 'ए' किस्म का 58.64 लाख मीट्रिक टन धान क्रमशः 1750 रुपये और 1770 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है।

64. लाभानुभोगियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के आधार पर मार्च 2018 से अम्बाला जिले के नारायणगढ़ और बराड़ा खण्डों में पोषणयुक्त आटे का वितरण शुरू किया है। अम्बाला जिले के नारायणगढ़ और बराड़ा खण्डों में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद अब यह योजना सम्पूर्ण अम्बाला और करनाल जिलों में लागू की गई है।

65. अब तक 29,51,701 (99.7 प्रतिशत) राशन कार्ड धारकों और 1,24,73,143 (98.2 प्रतिशत) आधार कार्ड लाभानुभोगियों को पीडीएस डाटाबेस में शामिल किया गया है। जुलाई 2017 से अब तक उचित मूल्य की दुकानों द्वारा गेहूं का वितरण आधार–बेस्ड बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण पद्धति से करने से लगभग 500

करोड़ रुपये की सबसिडी की बचत हुई है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बिना अनाज का एक भी दाना वितरित नहीं किया जा रहा है और हमारा राज्य आज पूरे देश में एक आदर्श राज्य बन गया है।

66. मेरी सरकार ने हेराफेरी को नियंत्रित करने और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए परिवार पहचान–पत्र डाटाबेस बनाने का निर्णय लिया है। इस डाटाबेस को आधार संख्या के साथ जोड़ा जाएगा और लगभग 46 लाख परिवारों को परिवार पहचान पत्र संख्या आबंटित की जा चुकी हैं।

माध्यमिक शिक्षा

67. मरी सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत कक्षा प्रबन्धन पर विशेष बल दिया गया है। तीसरी, पांचवीं और सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों का हिन्दी आर **गणित** में ग्रेड स्तर की योग्यता का आकलन करने के लिए सक्षम घोषणा –थर्ड पार्टी आकलन परीक्षा हर दो मास में एक बार आयोजित की जाती है। अब तक सक्षम घोषणा के 6 चरण आयोजित किए जा चुके हैं और 26 खण्डों को सक्षम घोषित किया गया है। पिछले 12 महीनों में औसत ग्रेड स्तरीय योग्यता प्रतिशतता में सुधार होने से यह 50–55 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

68. वर्ष 2018–19 के दौरान 31 राजकीय उच्च व माध्यमिक विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा दिया गया ह और निकट भविष्य में 50 से अधिक उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा। दर्जा बढ़ाये गये इन विद्यालयों के लिए अध्यापकों के नये पद भी स्वीकृत किये गये हैं।

69. छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 'छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना' शुरू की गई है। चयनित स्कूलों में छात्राओं को 'आत्म रक्षा प्रशिक्षण' दिया जा रहा है।

70. छात्राओं को अपने विचार सांझा करने के लिए सभी स्कूलों में बालिका मंच स्थापित किये गये हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक की सभी (लगभग 8 लाख) छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दियां प्रदान की गई हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है, जिसने हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण किया है।

उच्च शिक्षा

71. राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण अमले की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न विषयों के 1271 सहायक प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं। इस वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 36 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 26 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं। कुल 246 महाविद्यालयों व सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से 91 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं।

72. हमारे दो विश्वविद्यालया नामतः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा ग्रेड–I और ग्रेड–II की स्वायत्तता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 260.00 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

73. राज्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार ने भिवानी, जींद, गुरुग्राम और महेन्द्रगढ़ में नये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का काम शुरू किया है। करनाल के कुटल में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय' की स्थापना का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय में सुपर–स्पेशिलिटी विभाग, जैनेटिक्स, इम्यूनोलेजी, वायरोलॉजी में एडवांस रिसर्च सेंटर की सुविधा के अलावा एक अति आधुनिक ट्रॉमा सेंटर भी होगा।

74. राज्य सरकार वर्तमान शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, (नूंह) में एक डेंटल कॉलेज स्थापित कर रही है। इस परियोजना को 135 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया गया है।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

75. मेरी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कौशल विकास हेतु गुणवत्तापरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सत्र 2018–19 के दौरान प्रवेश के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 58,624 सीटें (30 प्रतिशत अतिरिक्त समेत) और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 34,144 सीटें जारी की गई हैं।

76. सत्र 2018–19 से 11 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्रेडिंग प्रक्रिया में 83 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने भागीदारी की।

77. चालू वित्त वर्ष में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 20,058 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु नियुक्त किया गया है। 16388 युवाओं को स्किलिंग अप–स्किलिंग री–स्किलिंग ऑफ यूथ एंड एसेस्मेंट स्कीम के तहत कुशल बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 16152 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और हमारा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले पांच राज्यों में से एक है। सक्षम युवा योजना के तहत 3860 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

स्वास्थ्य

78. मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को सस्ती, सुलभ, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 32 स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय

स्तर पर प्रमाणित किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसके जिला कुरुक्षेत्र के कृष्णानगर गामड़ी के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है।

79. जिला नागरिक अस्पताल, रोहतक ने राष्ट्रीय प्रमाणन में अधिकतम 96 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है और काजीरंगा (असम) में आयोजित 12 वें राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में सम्मानित किया गया। कायाकल्प कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के 332 स्वास्थ्य संस्थानों तक किया गया है, जिसके तहत 21 पीएचसी ने प्रथम रैंक हासिल किया है।

80. गैर–संचारी रोगों की रोकथाम पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, इसी का परिणाम है कि हमारे राज्य ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है।

81. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा बनाई गई और क्रियान्वित की गई उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन नीति की भारत सरकार द्वारा सराहना की गई है।नीति आयोग द्वारा आयोजित भारत के 115 पिछड़े जिलों के सम्मेलन में हरियाणा की इस नीति को प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में चुना गया।

82. इसके साथ ही, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने 100 प्रतिशत नाम आधारित उच्च जोखिम वाले गर्भवती मामलों की पहचान करने के लिए 'हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पोर्टल' नाम के एक अभिनव वेब एप्लिकेशन को तैयार और क्रियान्वित किया है।

83. राज्य में मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। मई 2018 में जारी नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात बुलेटिन के अनुसार, हरियाणा में मातृ मृत्यु अनुपात 26 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट से 101 हो गया है (नमूना पंजीकरण प्रणाली –2014–16)।

84. एसआरएस–2017 के अनुसार, हरियाणा ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 43 से 37 तक किया है, जो कि 6 अंकों की गिरावट है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर भी प्रति हजार जीवित जन्मों पर 36 से 33 हो गई है। यह कमी 3 अंकों की है, जबकि प्रति हजार जीवित जन्मों पर राष्ट्रीय मृत्यु दर 24 से घटकर 22 हुई है।

85. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2017 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य समीक्षा–सह–कार्यशाला के दौरान सांझा किए गए तथ्य पत्र के अनुसार एसएनसीयू देखभाल के गुणवत्ता संकेतक (एसक्यूसीआई) देशभर में सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए हरियाणा को सम्मानित किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने स्वयं के संसाधनों से 2 नवंबर, 2018 को निमोनिया की वैक्सीन शुरू की है, जिसके लिए पिछले वर्ष यूनिसेफ के साथ 84 करोड़ रुपये की निमोनिया की वैक्सीन की खरीद क लिए एक समझौता किया गया।

86. मेरी सरकार राज्य में सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य और दवाओं के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके अनुसरण में 11.41 करोड़

रुपये के बजट के साथ हरियाणा राज्य खाद्य प्रयोगशाला को अपग्रेड किया जा रहा है। सर्वेक्षण के साथ–साथ जनता के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की गई हैं।

आयुष

87. मेरी सरकार ने चिकित्सा की सदियों पुरानी आयुष पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। जीवन शैली जनित विकारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से विश्व स्तर पर और देश के अंदर आयुष चिकित्सा पद्धति में लोगों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। योग के महत्व को उजागर करने के लिए 21 जून, 2018 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया।

88. परम्परागत चिकित्सा पद्धति के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार ने देवरखाना (झज्जर) में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना करने का मुद्दा भारत सरकार के साथ उठाया है, जिसके लिए 83 कनाल भूमि निर्धारित की गई है। इसी तरह से पंचकूला में एक राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है। इस संस्थान में 250 बिस्तर होंगे और 500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी डिग्री प्रदान करने की सुविधा होगी।

89. इसके अलावा, जिला फरीदाबाद के गांव खेड़ी गुजरान में 120 बिस्तरों का यूनानी चिकित्सा का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। जिला हिसार के मय्यड़ में 50 बिस्तरों का राजकीय समेकित आयुष अस्पताल स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 15 एकड़ भूमि आयुष विभाग को दे दी गई है।

ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल

90. मेरी सरकार ने बहादुरगढ़ और बावल में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए ईएसआईसी, नई दिल्ली से अनुमोदन मिल गया है।

उद्योग और वाणिज्य

91. मेरी सरकार उद्योगों के लिए एक इको–सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन द्वारा निर्देशित है और राज्य के अनुरूप है और यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी उत्तम है। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर की एकल छत व्यवस्था के तहत समयबद्ध और वैधानिक तरीके से 70 से अधिक औद्योगिक मंजूरियां दी गई हैं। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर द्वारा शुरू की गई केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा देश में अपनाई जाने वाली प्रणालियों में सर्वोत्तम माना गया है।

92. मेरी सरकार ने मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान (2 करोड़

रुपये तक की परियोजना) दिया जाता है। इससे राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा।

93. कुण्डली–मानेसर–पलवल कॉरिडोर के साथ–साथ 'पंचग्राम' परिकल्पना के भाग के रूप में लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 शहरों के विकास पर सरकार कार्य कर रही है। इस परिकल्पना को गति देने के लिए पंचग्राम प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है।

खान एवं भूविज्ञान

94. मेरी सरकार ने खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने और सुव्यवस्थित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उचित दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही हैं। ई–नीलामी के माध्यम से छोटे खनन क्षेत्रों के आबंटन का सरकार का निर्णय एक पारदर्शी तरीका साबित हुआ और खनन क्षेत्र में रुचि रखने वाले छोटे उद्यमियों को भी अवसर मिला है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2018 तक 439.24 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया है।

श्रम विभाग

95. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान नवम्बर, 2018 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1,98,333 पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को 201.62 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है।

96. चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2018 तक हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा आधार सीडिंग बैंक खातों द्वारा डीबीटी के माध्यम स विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 19,724 श्रमिकों को 19.42 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन वितरित की गई है।

रोजगार

97. मेरी सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करके रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, रोजगार चाहने वालों के लिए विचार–विनिमय, सलाह और प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने तथा संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से रोजगार के आंकड़े एकत्र करने के लिए नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार मेले आयोजित किये
जाते हैं।

98. "शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय स्कीम–2016" नामक एक स्कीम पहली नवम्बर 2016 में शुरू की गई, जिसके तहत स्नातकोत्तर और स्नातक बेरोजगारों को क्रमशः 3,000 रुपये और 1,500 रुपये प्रति माह भत्ते के रूप में दिए जाते हैं और पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तर और स्नातक आवेदकों को मानद कार्य के लिए 6000 रूपये प्रति माह दिये जाते हैं। इस स्कीम के शुरू होने से

लेकर 31 दिसंबर, 2018 तक कुल 49,540 पात्र आवेदकों को मानद कार्य दिया गया है। 31.12.2018 तक बेरोजगारी भत्ता और मानदेय के लिए क्रमशः 188.63 करोड़ रुपये और 130.69 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है, जो 10+2 आवेदक या इसके समकक्ष और स्नातक या इसके समकक्ष सक्षम स्कीम के अंतर्गत नहीं आते उन्हें 'बेरोजगारी भत्ता योजना–2005' के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और 01.04.2018 से 30.09.2018 तक 26,320 लाभार्थियों को 17.92 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

99. 30.11.2018 तक 7,73,487 रोजगार चाहने वालों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। सक्षम हरियाणा अभियान के एक भाग के रूप में 16,332 बेरोजगार युवाओं को ओला और ऊबर के साथ समझौते के तहत कैब व टैक्सी ड्राइवरों (सक्षम सारथी) के रूप में नियुक्त किया गया है। 466 बेरोजगार युवाओं को सुरक्षा गार्ड (सक्षम रक्षक) के रूप में जी4एस के साथ एमओयू के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। मेरी सरकार के कार्यकाल में 31.12.2018 तक 335 रोजगार मेलों के माध्यम से 26,537 बेरोजगारों को विभिन्न निजी संगठनों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। विभाग स्वरोजगार पर भी विशेष बल दे रहा है। इसके लिए दिनांक 31.12.2018 तक 5243 आवेदकों को 80 ऋण मेलों व जागृति शिविरों में उद्यमशीलता के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई।

लोक निर्माण (भवन और सड़कें)

100. मेरी सरकार ने राज्य के सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समान और निष्पक्ष रूप से सड़क नेटवर्क सुधार के लिए एक कार्य योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में जरूरत के अनुसार सड़कों का सुधार हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए आरओबी व आरयूबी बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 18 आरओबी व आरयूबी का कार्य प्रगति पर है और 50 नए आरओबी व आरयूबी भारतीय रेलवे के साथ लागत हिस्सेदारी के आधार पर शुरू किये जा रहे हैं।

101. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 848.92 करोड़ रुपये की लागत की 886.82 किलोमीटर लम्बाई की 121 सड़कें स्वीकृत की गई है, इनमें से 772.13 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं।

102. मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के समय–समय पर रखरखाव के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 33.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। मेरी सरकार की पहल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1240.65 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग–148 (बी) के रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा)–नारनौल–महेन्द्रगढ़–चरखी दादरी–भिवानी भाग तथा एनएच–709 (ई) और भिवानी से खरक तक के भाग की कुल 155 किलोमीटर सड़क के फोर लेनिंग के कार्य को वर्ष 2016–2017 की अपनी वार्षिक योजना में शामिल किया था। पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ एनएच–21ए पर पिंजौर बाईपास के निर्माण के काम को भी मंजूरी दी गई है। 140 करोड़ रुपये लागत का यह कार्य प्रगति पर है।

103. भारत सरकार ने हमारे प्रदेश में 561 किलोमीटर की लंबाई की 7 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। इन सड़कों के अलावा 124.76 किलोमीटर को लंबाई की 4 सड़कों को भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इन सड़कों के अलावा दो सड़कों (ग्रीनफील्ड कॉरिडोर) यानि इस्माइलाबाद से नारनौल और सोहना से वडोदरा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

104. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हमारे प्रदेश में विभिन्न मेगा परियोजनाएं चला रहा है, जिनमें अंबाला से कैथल तक एनएच–65 की फोर लेनिंग, जींद–नरवाना–पंजाब सीमा सड़क (एनएच–71) की फोर लेनिंग, जिसमें जींद शहर का बाईपास भी शामिल है और मुकरबा चौक (दिल्ली) से पानीपत तक की 70 किलोमीटर लम्बी सड़क को 8 लेन करने के कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कैथल से राजस्थान सीमा तक एनएच–65 की फोर लेनिंग, 136 किलोमीटर लम्बे कुंडली–गाजियाबाद–पलवल एक्सप्रेस वे, एनएच–73 की फोर लेनिंग यानि पंचकूला से यमुनानगर तक के कार्य पहले ही पूरे कर लिये हैं। गुरुग्राम, पंचकूला और उचाना में नए लोक निर्माण विश्राम गृहों के भवनों को 2018 में पूरा किया गया है।

105. नई रेल पटरियां बिछाने और रेलवे से संबंधित अन्य निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच सांझाकरण आधार पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी (हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम) का गठन किया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

106. मेरी सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा और शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व वर्षा के पानी की निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्य व केंद्रीय योजनाओं के तहत 1789.49 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। 31.12.2018 तक 28 नहर आधारित जलघर, 466 ट्यूबवेल और 94 बूस्टिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। फर्रुखनगर, कालांवाली, मंडी–डबवाली, सफीदों, सिरसा में 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (5 एमएलडी) चालू किये गये हैं। महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, जींद, पलवल और मेवात जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड की सहायता से 1059.33 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। तीन अतिरिक्त परियोजनाएं, जिनकी लागत 236.85 करोड़ रुपये ह, पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं और वर्ष 2018–19 के दौरान इन पर 176.49 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

107. चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से 3 कस्बों नामतः फर्रुखनगर, नूंह और हेली मंडी–पटौदी में 205.05 करोड़ रुपये लागत की पेयजल आपूर्ति परियोजना चालू की गई है और सीवरेज की स्थिति में सुधार के लिए 72.11 करोड़ रुपये की लागत की 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। चालू वित्त वर्ष में 9 कस्बों अर्थात सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, गन्नौर,

होडल और समालखा में सीवरज की स्थिति में सुधार के लिए 9 परियोजनाओं पर 8.30 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

कला एवं सांस्कृतिक मामले

108. राज्य में कला, विरासत और संस्कृति तथा कलाकारों को प्रोत्साहन व मान्यता देने के लिए कला एवं सांस्कृतिक मामलों पर 'क्लश' (कला एवं संस्कृति हरियाणा) राज्य नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। कला की सभी विधाओं के कलाकारों का पंजीकरण व सूचीकरण किया जा रहा है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

109. पुरानी तहसील नूंह, धरोंद खेड़ा (जींद), मकबरा परिसर तावडू (नूंह), होडल (पलवल) में सती का तालाब एवं छतरी और लोहारू (भिवानी) का किला, सोहना (गुरुग्राम) में लाल गुम्बद एवं कुतुबखान की मस्जिद को राज्य संरक्षित स्मारक/स्थल घोषित करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचनाएं प्रकाशित की जा चुकी है। नूंह में शेख मूसा की दरगाह एवं झूलती मीनार को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए अंतिम अधिसूचना को प्रकाशित किया गया है।

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण

110. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, विमुक्त एवं टपरीवास जाति के (बीपीएल) परिवार को 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत दी जाने वाली शगुन राशि को 41,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। चालू वर्ष के दौरान 9,767 लाभार्थियों पर 34.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

111. 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना' के तहत अनुसूचित जाति के परिवार के सदस्य के साथ अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे 729 दम्पत्तियों को 4.90 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई है।

112. विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। ऐसे 2,727 उम्मीदवारों पर 4.52 करोड़ रुपये की राशि कोचिंग देने पर खर्च की गई है।

113. पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार की 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऐसे 33,318 विद्यार्थियों पर 87.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2009 छात्रों को लगभग 1.40 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।

114. सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए 'सफाई कर्मचारी आयोग' का गठन किया गया है।

कानून एवं व्यवस्था

115. मेरी सरकार ने पुलिसकर्मियों की पारदर्शी भर्ती को बहुत महत्व दिया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्तुति पद्धति पर राज्य में पुलिस में सिपाहियों और उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती शुरू की गई है।

116. पुलिस बल को आधुनिक, जवाबदेह तथा और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण पहलों–'मित्र कक्ष' और 'हरियाणा डायल 100' की योजना चलाई जा रही हैं। 'मित्र कक्ष' एक अनूठी पहल है, जिसमें त्वरित एवं कुशल सेवा प्रदायगी तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक अनुकूल इको सिस्टम उपलब्ध करवाया गया है। 'हरियाणा डायल 100' समस्त राज्य में पुलिस आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा, जिसे सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे किसी भी शिकायत को प्राप्त करने और उसकी निगरानी करने वाले केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संचालित किया जाएगा।

117. हरियाणा पुलिस का भारत के तीन सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होने के लिए पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। हरियाणा पुलिस को प्रशिक्षण के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन और मानक एवं दिशा–निर्देश श्रेणी प्रवर्तन में सर्वश्रेष्ठ आचरण के लिए सम्मानित किया गया है।

118. मेरी सरकार यह मानती है कि कल्याणकारी राज्य में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य के सभी जिलों में 30 नये महिला पुलिस थानों और प्रत्येक महिला पुलिस थाने में 30 क्रेचों की स्थापना की स्वीकृति की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को कम करने के लिए दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दुर्गा शक्ति वाहिनी का गठन किया गया है।

जेल एवं न्याय तंत्र

119. वादियों की सुविधा और मुकद्दमों के त्वरित निपटान के लिए मेरी सरकार ने विवाद प्रबंधन प्रणालो की शुरुआत की है। यह प्रणाली विभिन्न सरकारी एजेंसियों से सम्बन्धित मामलों की स्थिति, विभिन्न विभागों के मामलों की ई–वैटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैटिंग और ई–हिरासत प्रमाणीकरण शुरू किया है, जिससे राज्य की 19 जेलों से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिरासत प्रमाणीकरण प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों से अनावश्यक स्थगन से बचा जा रहा है। शीर्ष न्यायालय द्वारा इन पहलों की सराहना की गई है।

सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण

120. मेरी सरकार रक्षा कार्मिकों, पूर्व–रक्षा कार्मिकों, अर्ध–सैनिक बलों के कार्मिकों के साथ–साथ उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। चालू वर्ष में युद्ध में शहीद हुए वीरों के 63 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गईं हैं। भारत सरकार द्वारा दी जा रही पारिवारिक पेंशन के अलावा रक्षा बलों के

कर्मियों की युद्ध विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 400 रुपये वार्षिक की वृद्धि की जाती है।

121. रेवाड़ी में 24 करोड़ रुपये की लागत से एक नये सैनिक स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है। कुंजपुरा के सैनिक स्कूल के उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मातनहेल में नए सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय को समझौता ज्ञापन का प्रारूप भेजा गया है, इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खेल एवं युवा मामले

122. मेरी सरकार ने राज्य में अक्तूबर–नवम्बर 2018 में 15 खेलों में महाकुंभ नामक जिला व राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को उसी समय नकद पुरस्कार प्रदान किये गये। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर 21 से 23 मार्च तक भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पाने वाले पहलवानों को क्रमशः 1 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 10 लाख रूपये के नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। इसी तरह से पंडित दीन दयाल उपाध्याय अखिल भारतीय नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें विजेताओं को उपरोक्त नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।

123. मेरी सरकार खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। राज्य में दो स्विमिंग पूल, एक बहुउद्देशीय हॉल, चार सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, दो हॉकी एस्ट्रो–टर्फ और एक फुटबॉल सिंथेटिक सरफेस निर्माणाधीन हैं।

परिवहन विभाग

124. मरी सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षित, किफायती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। 367 साधारण गैर एसी बसों और 150 एचवीएसी बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुरानी खराब बसों के स्थान पर चालू वर्ष के दौरान 164 नई बसें शामिल की गई हैं। 470 लिपिकों के अतिरिक्त, 1717 ड्राइवरों और 880 कंडक्टरों की नियमित आधार पर भर्ती की गई है। हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं व डिपुओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्रुप डी के 544 कर्मचारियों की भर्ती की है।

125. एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पीपीपी मोड पर राजीव चौक, गुरुग्राम में नये बस अड्डे के विकास की प्रक्रिया भी शुरू की है। मेरी सरकार हरियाणा राज्य परिवहन में इलैक्ट्रोनिक टिकट जारी करने की परियोजना, आरएफआईडी आधारित बस पास प्रणाली और जीपीएस प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'निभया निधि योजना' के तहत 100 एचवीएसी बसें (पिंक एक्सप्रेस) खरीदने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ये बसें केवल अकेली अथवा एक साथी

के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए होंगी और इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी।

126. स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए 'सुरक्षित स्कूल वाहन नीति' लागू की गई है। स्कूल बसों में आईपी कैमरा और जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। मेरी सरकार ने कालूवास (भिवानी), छपरा (नूंह), जयसिंहपुर खेड़ा (रेवाड़ी) और उचानी (करनाल) में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान के चार और संस्थान स्वीकृत किये हैं। परिवहन और गैर–परिवहन दोनों तरह के वाहनों के लिए, दो पहिया वाहन के लिए पांच वर्ष हेतु थर्ड पार्टी बीमा और कारों के लिए तीन वर्ष का बीमा अनिवार्य कर दिया गया है।

127. हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 दिनांक 28.11.2018 को अधिसूचित किये गये हैं। इनमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि कम्पोजीशन शुल्क का 50 प्रतिशत सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। चालू वर्ष में चालान कम्पोजीशन फीस से एकत्रित 150 करोड़ रुपये की राशि में से 75 करोड़ रुपये सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए आवंटित किये गये हैं ।

नागरिक उड्डयन

128. मेरी सरकार ने राज्य में हवाई खेल गतिविधियां शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में, ऐसी गतिविधियां तीन महीनों की अवधि के लिए वाणिज्यिक ट्रायल आधार पर बाछौद (नारनौल) हवाई पट्टी (हॉट एयर बैलूनिंग, पैरा सेलिंग) में शुरू की गई हैं। पिंजौर, करनाल, भिवानी और नारनौल में मौजूदा हवाई पट्टियों का विस्तार करने के लिए उनकी 3,000 फुट लम्बाई को 5,000 फुट करने का निर्णय भी लिया जा रहा है।

आबकारी एवं कराधान

129. मेरी सरकार ने राज्य में वस्तु एवं सेवा कर को सुचारू ढंग से लागू किया है। सरकार ने जिला स्तर पर व्यापारियों से सम्बन्धित मुद्दों के निपटान के दृष्टिगत राज्य के हर जिले में व्यापारी परामर्श समितियां गठित करने का निर्णय किया है। राज्य के सभी पंजीकृत डीलरों के लिए दो अलग–अलग समूह बीमा योजनाएं विचाराधीन हैं, जिनके माध्यम से उन्हें आकस्मिक मृत्यु के मामले में या भूकंप, आग, चोरी, डकैती और दंगों के मामले में क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। कर दाताओं और सरकारी तंत्र के बीच मानव हस्तक्षेप न्यूनतम करने के दृष्टिगत मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि आबकारी और वैट कार्य की विरासत की सभी गतिविधियां विभाग के पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएं।

130. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर आम जनता को राहत देने के लिए मेरी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से राज्य में 04.10.2018 से डीजल पर वैट की दर 17.22 प्रतिशत से घटाकर 13.90 प्रतिशत और पेट्रोल पर 26.25 प्रतिशत से घटाकर 23.37 प्रतिशत की है ताकि उपभोक्ताओं को 5 रुपये प्रति लीटर की तत्काल राहत मिले। औद्योगिक विनिर्माताओं को राहत देने के लिए पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पर वैट की दर 24.04.2018 से 12.5

प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। क्षेत्रीय संयोजिता स्कीम को प्रोत्साहित करने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट की दर 01.08.2018 से 21 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत (एटीएफ) कर दी गई है।

131. वैट, एलएडी, मनोरंजन कर आदि की बकाया राशि की वसूलो के लिए गत वर्ष 'हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम–2017' शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत बकाया 2,328.36 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसी तरह से ठेकेदारों के लिए 'हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम'' 02.06.2017 संशोधित की गई। इसके फलस्वरूप इस स्कीम के तहत डेवलपर्स और बिल्डर्स से
833.31 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई।

132. कर से बचाव, भ्रष्ट पद्धतियां और कर संग्रह पद्धति में अनियमितताओं की जांच में मदद करने के लिए डिजिटल डेटा के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने के लिए एक कर अनुसंधान इकाई की स्थापना की गई है।

वन

133. वन विभाग ने पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार के सहयोग से मोरनी की पहाड़ियों में एक हर्बल वन की स्थापना की है, जहाँ विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे हैं।

134. मेरी सरकार ने जिलों में पौधागिरी अभियान चलाया है और बच्चों को पेड़ –पौधे लगाने व पेड़ों को बचाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस अभियान के तहत, छठी से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों ने अपने घरों या आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाए हैं।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

135. पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए और आम जनता को संवेदनशील बनाने व उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रदूषण मुक्त रखने हेतु, चार प्रमुख परियोजनाएं, जैसे कि 'स्केलिंग–अप क्लाइमेट स्मार्ट विलेज', ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूल भवन, में कृषि जैव विविधता पार्क का विकास और सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हरियाणा को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करना है।

136. इको क्लब विद्यालयों में पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य भर से 50 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है। घग्गर नदी को प्लास्टिक से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया और घग्गर से 150 टन (गीला) कचरा निकाला गया। पर्यावरण की बेहतर निगरानी और अनुसंधान के लिए जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने हेतु रणनीतिक ज्ञान केंद्र, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी सेल, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान तथा पर्यावरण सूचना पद्धति हब (इएनवीआईएस) नामक चार नए संस्थान स्थापित किये गये हैं।ण

सहकारिता

137. 97वें संविधान संशोधन के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने तथा सभी सहकारी समितियों के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण के गठन पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है, जिसका अध्यक्ष राज्य सहकारी चुनाव आयुक्त होगा।

138. 400 करोड़ की अनुमानित लागत से सह–उत्पादन तथा रिफाईंड चोनी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ 5000 टीसीडी की एक नई चीनी मिल पानीपत में स्थापित की जा रही है, जिसे एक वर्ष में पूरा किया जाएगा। हैफेड ने आईएमटी रोहतक में 179.75 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से एक मेगा फूड प्रोजेक्ट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.40 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध संयंत्र जींद में दही बनाने की इकाई का उद्घाटन किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

139. मेरी सरकार ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई–गवर्नेंस सेवाओं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करने के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' में बड़ी प्रगति की है। नागरिकों के घर–द्वार पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 16,141 अटल सेवा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं।

140. मेरी सरकार अब 37 सरकारी निकायों की 425 सरकारी सेवाएं 'सरल' प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिकों को प्रदान कर रही है और 107 सेवाओं को भारत सरकार के 'उमंग' एप्प के साथ जोड़ा गया है ।

141. डिजी–लॉकर पर 50 लाख दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, जिनमें शैक्षिक प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड आदि शामिल हैं। इससे नागरिकों के दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध होगी। हरियाणा मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, गुरुग्राम में तीन इनक्यूबेशन सैंटर स्थापित किए गए हैं और इन इनक्यूबेटर में 41 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। एसटीपीआई के सहयोग से एक और इनक्यूबटर सैंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य के 7 विश्वविद्यालयों में 7 और इनक्यूबेटर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

142. राज्य में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और बड़ी–बड़ी आंकड़ा परीयोजनाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार की सहायता हेतु मेरी सरकार ने गुरुग्राम में यूनाईटिड नेशन टैक्नोलॉजी इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से समझौता किया है।

143. मेरी सरकार नेशनल रिमोट सेंसिंग (इसरो) के सहयोग से जियो रैफरैंस का उपयोग करके प्रभावी सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। इस परियोजना की शुरुआती सफलताओं मं से एक हरपथ मोबाइल एप्प है, जो नागरिकों को सड़क की स्थिति जैसेकि क्षतिग्रस्त सड़क और दुर्घटना सम्भावी स्थानों की अवस्थिति आधारित और चित्र सहित जानकारी देने में सक्षम बनाता है।

144. मुझे आपके साथ यह सांझा करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारा राज्य आधार बाल नामांकन में प्रथम है और आधार आधारित बॉयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अग्रणी है। हरियाणा साइबर सुरक्षा नीति फ्रेमवर्क और कैशलेस हरियाणा समेकन पोर्टल को कई मंचों पर सम्मानित किया गया है।

सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा

145. वर्तमान सरकार हरियाणा को फिल्म सम्बन्धी गतिविधियों के हब के रूप में विकसित करने के कार्य में लगी है। हरियाणा को फिल्म मैत्री राज्य बनाने के लिए एक फिल्म नीति लागू की गई है। फिल्मी जगत को आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने एवं राज्य में फिल्म निर्माण आधार स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु औपचारिकताओं को पूरा किया गया है ताकि हरियाणा की समृद्ध एवं गौरवशाली परम्पराओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया जा सके। फिल्म नीति हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें हरियाणवीं भाषा और संस्कृति पर आधारित फिल्में बनाने वाले हरियाणा के कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

146. सरकार द्वारा एक और सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक महीने में कम से कम एक सुधार लागू करना है। मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने के लिए 'मुख्यमंत्री से सीधी बात' कार्यक्रम शुरू किया गया है।

पर्यटन

147. भारत सरकार ने अपनी 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु 'कृष्णा सर्किट' के तहत कुरुक्षेत्र का चयन किया है। तदानुसार मेरी सरकार ने ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर और कुरुक्षेत्र के शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजना बनाई है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस प्रस्ताव के विरूद्ध मेरी सरकार ने 99. 51 करोड़ रूपये की विस्तृत योजना भारत सरकार को भेजी है, जिसके लिए भारत सरकार ने 97.34 करोड रूपये स्वीकृत कर दिये है और इसमें से अब तक 70.59 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है ।

148. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश दर्शन योजना के 'कृष्णा सर्किट' के द्वितीय चरण में 33.45 करोड़ रुपये की राशि से कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और मेवात में श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थ स्थानों के पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा कुरुक्षेत्र में 'गीता ज्ञान संस्थान' के विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत 29.60 करोड़ रुपये की राशि से रेवाड़ी–महेन्द्रगढ़–माधोगढ़ के लिए 'हैरीटेज सर्किट' के तहत पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास का काम शुरू किया जा रहा है। तीर्थ यात्रा जोर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत 11.12 करोड़ रुपये की राशि से 'नाडा साहिब गुरुद्वारा परियोजना' का विकास का मामला भारत सरकार के सामने उठाया जा रहा है।

149. मेरी सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति तथा स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना–2017 (श्री हुजूर साहिब, नांदेड़ साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब) के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया हुआ है। यह वित्तीय सहायता 50 व्यक्तियों व तीर्थ यात्रियों तक दी जा रही है।

माननीय सभासदो

150. मैने अपने अभिभाषण में आपके साथ कार्यक्रमों और नीतियों का जो विस्तृत विवरण सांझा किया है, उससे 'सबका साथ–सबका विकास' और 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी की समद्धि के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। वास्तव में, आम आदमी द्वारा इन नीतियों के जबरदस्त समर्थन का स्पष्ट प्रमाण हाल ही में सम्पन्न हुए पांच नगर निगमों नामतः हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर के मेयर और पार्षदों के चुनाव और 37–जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणामों से मिलता है।

151. अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपसी सम्मान और सौहार्द दिखा कर इस सदन ने अपने देश की लोकतंत्र की उच्चतम परंपराओं को बनाए रखने का प्रयास किया है। जन सरोकारों के मुद्दों पर विचार–विमर्श और बहस के माध्यम से आप हरियाणा के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी लोगों, विशेषकर पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के महान कार्य में समर्पित मेरी सरकार का सहयोग करें।

वंदे मातरम !

जयहिन्द !

.....

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, ऐसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

श्री जॉर्ज फर्नांडिस, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस के 29 जनवरी, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून, 1930 को हुआ। वे वर्ष 1967, 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 तथा वर्ष 2004 में नौ बार लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1977–79, 1989–90 तथा वर्ष 1998–2004 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे। उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए रक्षा, रेलवे, उद्योग तथा संचार जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2009 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुये। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। वे मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

सरदार जसविंद्र सिंह संधू , हरियाणा विधान सभा के सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य सरदार जसविंद्र सिंह संधू के 19 जनवरी, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 अगस्त, 1955 को हुआ। वे वर्ष 1991, 1996, 2000 तथा वर्ष 2014 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 2000–05 के दौरान मंत्री तथा वर्ष 1999–2000 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। उन्हें मत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, उद्यान तथा भू–संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री सीता राम सिंगला, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सीता राम सिंगला के एक जनवरी, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 अगस्त, 1941 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1987–89 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मत्रिमंडल में रहते हुए खेल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री वेद सिंह मलिक, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के 17 जनवरी, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 जून, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्ष 1990–91 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री भागमल यादव, गांव कुकरोला, जिला गुरुग्राम।
2. श्री जुगलाल आर्य, गांव धारवाणबास, जिला भिवानी।
3. श्री भलेराम, गांव हसनगढ़, जिला हिसार।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

––––––

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. विंग कमांडर साहिल गांधी, हिसार।
2. सहायक उप निरीक्षक सतपाल सिंह, गांव दिल्लूवाला, जिला जींद।
3. हवलदार ब्रिजेश कुमार यादव, गांव नांधा, जिला रेवाड़ी।
4. हवलदार बलजीत सिंह, गांव डिंगर माजरा, जिला करनाल।
5. हवलदार सुरेश कुमार, गांव सेहलंगा, जिला झज्जर।
6. नायक शक्ति सिंह, गांव बौंदकलां, जिला चरखी दादरी।
7. नायक संदीप कुमार, गांव अटाली, जिला फरीदाबाद।
8. सिपाही राय सिंह, गांव अटेला कलां, जिला चरखी दादरी।
9. सिपाही रामराज, गांव सिलानी कैसो, जिला झज्जर।
10. सिपाही कैलाश चंद्र, गांव बिलोचपुरा, जिला झज्जर।
11. सिपाही रतन सिंह, गांव पुट्ठी मंगलखां, जिला हिसार।
12. सिपाही रमेश कुमार, गांव गोपालवास, जिला भिवानी।
13. सिपाही हरि सिंह, गांव राजगढ़, जिला रेवाड़ी।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

––––––

जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में हुए शहीद

यह सदन 14 फरवरी, 2019 को जम्मू–कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. के वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निन्दा करता है और महान वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है।

यह सदन शहीदों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन

राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर की सास, **श्रीमती फूलावंती**;

विधायक श्री करण सिंह दलाल के भांजे, **श्री सतेंद्र रावत**;

पूर्व मंत्री श्री चंदा सिंह के पुत्र, **श्री शमशेर सिंह**;

पूर्व मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के भाई, **श्री सतबीर सिंह**;

पूर्व विधायक श्री नरेश यादव के पिता, **श्री शेर सिंह**;

तथा

पूर्व विधायक श्री आनन्द कौशिक की माता, **श्रीमती वैष्णो देवी** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

इसके अलावा 20 फरवरी, 2019 को जिला झज्जर के गांव राईया के पास सड़क दुर्घटना में मारे गए एक ही परिवार के 4 सदस्य व एक अन्य यानी कुल 5 नागरिकों के हुए दुखःद एवं असामयिक निधन पर भी यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला शोक प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : स्पीकर सर, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में पढ़े हैं उनमें मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी शामिल करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्री जॉर्ज फर्नांडिस, भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री, सरदार जसविंदर सिंह संधू, हरियाणा विधान सभा के सदस्य एवं भूतपूर्व मंत्री, श्री सीताराम सिंगला, भूतपूर्व राज्य मंत्री और श्री वेद सिंह मलिक, भूतपूर्व राज्य मंत्री के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में हुए शहीद वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसके साथ–ही–साथ हरियाणा के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको भी मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ–साथ इस सदन के माननीय सदस्यों के परिवार के जो सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे इन सभी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारी पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया है कि वे अपनी एक महीने की तनख्वाह उन शहीदों के परिवार वालों को देंगे। जब कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं या प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी एक महीने की तनख्वाह उनके परिवार वालों को देते हैं, इसीलिए आज हमने यह फैसला लिया है।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदन के नेता ने जो 1 नं० से लेकर 9 नं० तक शोक प्रस्ताव पढ़े हैं हमारी कांग्रेस पार्टी भी अपने आपको उनसे जोड़ती है। इस शोक प्रस्ताव के अंदर श्री जॉर्ज फर्नांडिस जो भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं, सरदार जसविंद्र सिंह संधू जो हरियाणा विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, के निधन पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करती है। मैं संधू जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मैंने हमेशा यह देखा है कि जब भी सदन की कार्यवाही होती थी और उसमें जब भी किसी माननीय सदस्य द्वारा गलत बात कही जाती थी तो ये उसमें बढ़–चढ़कर अपनी आवाज उठाते थे और बहुत ही सहज ढंग से अपनी बात रखते थे। उन्होंने कभी भी इस सदन में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो सदन की

परिपाटी के खिलाफ हो। इसके साथ ही साथ श्री सीता राम सिंगला जी जो हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री थे, उनके प्रति भी मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। इसके साथ ही साथ श्री वेद सिंह मलिक जी जो हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री थे, के प्रति भी मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करती हूं। इसके साथ ही साथ हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके प्रति भी हम शत्–शत् नमन करते हैं और उनके शोक–संतप्त परिजनों के प्रति मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–ही–साथ हरियाणा के जो वीर शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत पर उनको भी शत्–शत् नमन करते हैं और उनके शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जो आतंकवादी हमला हुआ, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी कि the nation stands in solidarity against Pakistan and we speak in one voice at the way the CRPF Jawans were killed in Pulwama. I think it is a time to give a befitting reply to Pakistan at this point of time because we have seen, during the past 5 years the steady escalation of activity of these terrorist attacks on our country. So, it is time that all kinds of talks whatever we are doing with them and whatever is happening between the two countries, that should be stopped and a befitting reply should be given to them. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–ही–साथ मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर की सास, श्रीमती फूलावंती, विधायक श्री करण सिंह दलाल के भांजे, श्री सतेंद्र रावत, पूर्व मंत्री श्री चंदा सिंह के पुत्र, श्री शमशेर सिंह, पूर्व मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के भाई, श्री सतबीर सिंह, पूर्व विधायक श्री नरेश यादव के पिता, श्री शेर सिंह, तथा पूर्व विधायक श्री आनन्द कौशिक की माता, श्रीमती वैष्णो देवी के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती हूं। इसके साथ–ही–साथ मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से जिला झज्जर के रैया गांव के पास सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी

के सभी विधायकगणों ने एक फैसला किया है कि शहीदों के परिवारजनों को एक महीने की सैलरी देंगे और इसके अलावा हमारे विधायकगणों ने यह भी फैसला किया है कि भविष्य में इन परिवारों के लिए जो बन सकेगा वह भी करने की पूरी कोशिश करेंगे ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हमारे पलवल शहर में हजारों नौजवानों ने पाकिस्तान के विरोध में जुलूस निकाला था। जुलूस निकालते वक्त बिजली विभाग की लापरवाही से दो गरीब नौजवानों की करंट लगने से मौत हो गई थी । उनके नाम इस प्रकार हैं श्री ढेनी पुत्र श्री रामजी लाल, निवासी गली नम्बर 5–वार्ड, नम्बर–5 मोहन नगर, पलवल और श्री बोबी पुत्र श्री गब्बर, निवासी वार्ड नम्बर 5, राजीव नगर, पलवल । अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि ये बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे थे और नट समाज से सम्बन्ध रखते थे । उनके सिवाय इनके परिवार में आगे कोई भी कमाने वाला नहीं है । मेरा आग्रह है कि इनके परिवारों वालों को विधान सभा की तरफ से श्रद्धांजलि भी दी जाये और सरकार से जो संभव हो सके उनकी आर्थिक मदद भी की जाये ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य होने के नाते नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला की इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो शहीद हुए सैनिकों के परिवारजनों को सहायता स्वरूप एक महीने की सैलरी देने की बात कही गई है । अध्यक्ष महोदय, हमारा भी यह फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य पुलवामा में हुए शहीदों के परिवारजनों की सहायता के लिए एक महीने की सैलरी देंगे। मेरा निवेदन है कि श्री करण सिंह दलाल जी ने जिन गरीब परिवार के बच्चों के नाम दिये हैं उनके नाम भी शोक प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिए जाएं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी जो अपनी–अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन सभी

दिवगंत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें । माननीय सदस्यगण, मैं इस सदन की भावनाओं को उन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर कायराना आतंकी हमले से संबंधित निंदा प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलवामा में कायरतापूर्ण हमले के बारे में एक निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> ''कि यह सदन दिनांक 14 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के द्वारा पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले, जिसमें 42 जवान शहीद हुए, की घोर निन्दा करता है और इस दुःख की घड़ी में यह सदन सभी शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
>
> यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें'' ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> ''कि यह सदन दिनांक 14 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के द्वारा पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले, जिसमें 42 जवान शहीद हुए, की घोर निन्दा करता है और इस दुःख की घड़ी में यह सदन सभी शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
>
> यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें'' ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> ''कि यह सदन दिनांक 14 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के द्वारा पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले, जिसमें 42 जवान शहीद हुए,

की घोर निन्दा करता है और इस दुःख की घड़ी में यह सदन सभी शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का दुश्मन को मूंह तोड़ जवाब दे'' ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सर्वसम्मति से पारित हुआ)

बैठक का स्थगन

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक सिटिंग एम.एल.ए. स्वर्गीय सरदार जसविन्द्र सिंह संधू, का स्वर्गवास हो गया है । मेरा आपसे निवेदन है कि उनके निधन पर सदन की बैठक को आज के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप स्थगित कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को पता है कि जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर जैश–ए–मोहम्मद आतंकी संगठन द्वारा कायरतापूर्ण हमले में 42 सैनिक शहीद हो गये हैं और हमारे सिटिंग विधायक श्री जसविन्द्र सिंह संधू का भी स्वर्गवास हो गया है इसलिए यदि हाउस की सहमति हो तो इन सभी के सम्मान में सदन स्थगित कर दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और आज की लिस्ट ऑफ बिजनैस में फिक्स्ड बाकी कार्य वीरवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 की बैठक में टेक–अप किये जायेंगे।

*15.05 बजे

(तत्पश्चात् सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)